[Shri George Fernandes]

the attention of the House to one more instance of the way the National Security Act is used to harass and brow-beat trade union workers.

Mr S. C. Datta, driver and Mr. Newton Eliza, shunter are active trade union workers among the loco running staff at Ajni near Nagpur. Apparently, orders for their detention under the National Security Act were issued on January 28, 1981 along with similar detention orders for other workers. This was at the time of the loco running staff strike. However, for reasons best known to the police, they were not arrested.

The strike of the loco running staff was called off towards the end of February 1981. Both Mr. Datta and Mr. Eliza were allowed to resume duty on 6th and 7th of June 1981 respectively. They were kept attached to the office, and not posted on running duty.

Now, two and a half months after they resumed duty, Mr. Datta has been detained on 26th August and Mr. Eliza on 28th August, under the National Security Act.

The action of whosoever it is that ordered their arrest is patently mala fide and needs to be condemned in the strongest possible language.

I urge that the Home Minister take steps to order the immediate release of these two railwaymen,

(iv) NEED FOR DEVELOPMENT OF IRRIGATION SYSTEM IN CHHATIS-GARH AREA OF MADHYA PRADESH.

अो कैयर भूषण (रावपुर) : मान्यवर मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा जो छत्तीसगढ के नाम से जाना जाता है जहा म्रादिवासियों एवं हरिजनों की संख्या अधिक है आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। विगत कुछ वर्षों से उस क्षोत्र में ग्रकाल पड़ रहा है। उस क्षेत्र के

ग्रामीण खेतिहर मजदूर मजदूरी की तलाश में छत्तीसगढ छोड घर पलायन कर जाते हैं। उन्हें दूरस्य स्थानों में बहुत कठिन स्थिति में जीवन बिताना पड़ रहा है। मजबरी का फायदा उठा कर मजदूर भरती करने वाले दलाल पैदा हो। गए हैं। वे उन्हें उचित मजदूरी की लालच बता सपरिवार ले जाते हैं तथा ठेकेदारीं के पास बंधक मजदूर के रूप में रख देते हैं। उन्हें जीवन यापन के लिए उन प्रदेशों में ठेकेदारों के यहां धाजीवन बंधक रहना पड़ता है। उन्हें वहां नाम-माल की मजदूरी मिलती है। घर वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें डरा धमका कर रखा जाता है तथा उनके मजदूरी के पैसे उन्हें दिए नहीं जाते। उनके जीवन रक्षा का प्रबन्ध वहां की सरक र किसी प्रकार की नहीं कर रही है। न ही उन्हें मुक्त करने की व्यवस्था कर रही है और न हो उन्हें छत्तीसगढ मध्य प्रदेश के अन्तर्गत वापस लाने तथा जीवकोपार्जन की व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पुनः ग्रकाल की स्थिति है। प्रतः उस क्षेत्र के खेतिहर मजदूर पलायन करना प्रारम्भ कर दिए हैं। इसलिए शासन का ध्यान छत्तीसगढ़ की श्रकाल से मुक्ति दिलाने के लिए सिंचाई सविधा उपलब्ध कराने के लिए उस क्षेत्र के प्रस्तावित योजनायों को शीघ प्रारम्भ करें तथा वहां उचित मजदूरी व्यवस्था करे तथा छत्तीसगढ़ के मजदूर जो देश के विभिन्न हिस्सों में बंधक मजदूर बन कर जी रहे हैं विशेषकार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उन्हें शीघ्र मुक्त करावें।

(v) NEED FOR PAYMENT OF PENSIONS TO EX-SERVICEMEN AND FREE-FIGHTERS BY MONEY DOM ORDERS. 900

श्री महाबीर प्रसाद (बांसगांव) : मान्यवर, में ग्रापका ध्यान भतपूर्व सैनिकों

CONCLUSION STREET, SAN ENGINEERING THE RESERVE AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P

एवं स्वतंत्रता सेवानियों की पेंशन भूगतान के संबन्ध में ग्राक्षित करना चाहता है। श्रीमन भारत माता को गुलामी की जंजीरों से छड़ाने एवं उसकी सेवा करने के बाद जो भ्रतपूर्व सैनिक एवं स्वतंवता सेनानी ग्राने घरों पर निवास कर रहे हैं ग्रौर अपनी सेवाओं के बदले में भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा पैंशन प्राप्त करने के लिए माह के घन्त तक निगाह लगाये हए बैठे रहते हैं चाहे वे गोली खाकर अयंग हों गये हीं या बढे हो गए हो चाहे वे कर्तल मेजर कैंटन सूबेदार, हवलदार या साधारण सैनिकों के पद पर कार्य करके सेवा निवत हो गए हों माह के यन्त में वह काफी द्री तयकर के कचहरी में जाते हैं ग्रीर वे दिन, रात भर बैठे रहते हैं ग्रीर दूसरे दिन तक भी वे कचहरी में बैठे रह जाते हैं। ग्रंत में दो, तीन दिन के बाद वे भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी काफी अनादर एवं असम्मान के बाद अपनी पेंशन प्राप्त कर पाते हैं। जब कि बे इस कठिन समय में 20-30 रूपये खर्च कर देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था देश के प्रत्येक भागों में लागू हैं। विशेषकर उत्तराखंड मे गढ़वाल मंडल के रहने बाले भुतपूर्व सैनिक जो देशया मात्भूमि की रक्षा हेत् अपने प्राणी की बाजी लगा कर अपने जीवन निर्वाह हेतु पेंशन की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं ग्रीर उक्त कठिनाइयों के बाद वे अपनी पेंशन प्राप्त कर पाते हैं।

ग्रतः ग्रायके माध्यम से केन्द्रीय श्रीर राज्य सरकारों से जोरदार निवेदन है कि उक्त परेशानी को दूर करने के लिए मनीग्रार्डर द्वारा कमीशन काट कर उनकी पेंशन उनके घर पर भेजी जाये ताकि ससम्मान वे ग्रथनी पेंशन प्राप्त कर सके।

> (vi) Need for resumption of mining operations in all the coal Mines in Hazaribagh.

SHRIN.E. HORO (Khunti): Over 50,000 coalminers in South-Karanpura in the district of Hazaribagh (Bihar) were thrown out of jobs in the wake of nationalisation of coal industry when the Central Coalfied Ltd., closed nearly 30 small and medium coal mines. The local people including the displaced coalminers have been constantly demanding

The management of the Central Coalfield Ltd. have so for refused to open the mines for reasons not known. These would have led to illegal mining which goes on unabated resulting in the loss of the national exchequer.

opening of these closed coalmines in order to earn their daily bread.

The demand of the people for opening the closed mines is but genuine since they want an honourable employment anddo not want to join he gangs of illegal miners.

In this connection, the demand to start the Balrampur Colliery in Village Urimari by open-cast mining is pending with the Ministry of Energy. People want open-cast mining and not mechanisation mining since that would debar them for getting gainful employment. It is at this place, on this question that firing took place last February where a dozen of persons were killed.

I draw the attention of the Government of India to take necessary steps to open all closed mines including Balrampur (Urionari) Colliery and give employmentto the local people.

ATROCITIES BY (vii) ALLEGED POLICE IN UTTAR PRADESH BIHAR AND MADHYA PRA-DESH ON PERSONS BELONG-ING TO BACKWARD CLASSES MINORITIES ETC. TO SELECT

भी जयपाल सिंह कश्यप (ग्रावला) : उपाध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश, बिहारः व मध्य प्रदेश में पूलिस ने 2,3 वर्षो से झुठी व फर्जी मुठभेडें दिखाकर हजारों सीमों की हत्या कर दी। इन में ग्रधिकाँश कमजोर वर्ग हरिजन, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक किसान मजदूर वर्ग के